## All Online Learning www.allonlinelearning.com

## Part XVI: Special Provisions relating to certain classes

Part XVI of the Constitution of India deals with Special Provisions relating to certain classes. It contains provisions regarding the rights and interests of various marginalized and historically disadvantaged groups, including Scheduled Castes and Tribes, Anglo-Indians, and other minority communities.

Article 330 provides for the reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Legislative Assemblies of the States and in the House of the People (Lok Sabha), and lays down the provisions regarding the manner in which such reservations are to be made.

Article 331 provides for the reservation of seats for Anglo-Indians in the Legislative Assemblies of the States and in the Lok Sabha, and lays down the provisions regarding the manner in which such reservations are to be made.

Article 332 provides for the reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Legislative Assemblies of the States and in the Lok Sabha in case the number of seats in such Assemblies or the Lok Sabha is increased, and lays down the provisions regarding the manner in which such reservations are to be made.

Article 333 provides for the reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Legislative Councils of States having such Councils, and lays down the provisions regarding the manner in which such reservations are to be made.

Article 334 provides for the reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes to cease to exist after a period of ten years from the commencement of the Constitution, but this period has been extended by subsequent amendments to the Constitution.

Article 335 provides for the claims of the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to services and posts, and lays down the provisions regarding the protection of such claims.

Overall, Part XVI of the Constitution of India lays down the provisions regarding the rights and interests of various marginalized and historically disadvantaged groups, including Scheduled Castes and Tribes, Anglo-Indians, and other minority communities, and aims to ensure the protection and promotion of their rights and interests.

भाग XVI: कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान

भारत के संविधान का भाग XVI कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों से संबंधित है। इसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों, एंग्लो-इंडियन और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों सहित विभिन्न हाशिए पर पड़े और ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के अधिकारों और हितों के संबंध में प्रावधान हैं।



www.allonlinelearning.com

## All Online Learning www.allonlinelearning.com

अनुच्छेद 330 राज्यों की विधानसभाओं और लोक सभा (लोकसभा) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है, और इस तरह के आरक्षण के तरीके के बारे में प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 331 राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभा में एंग्लो-इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है, और इस तरह के आरक्षण के तरीके के बारे में प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है और ऐसी विधानसभाओं या लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ने की स्थिति में लोकसभा में, और तरीके के बारे में प्रावधान करता है जिसमें इस तरह के आरक्षण किए जाने हैं।

अनुच्छेद 333 ऐसी परिषदों वाले राज्यों की विधान परिषदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है, और इस तरह के आरक्षण के तरीके के बारे में प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 334 संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अविध के बाद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का अस्तित्व समाप्त करने का प्रावधान करता है, लेकिन संविधान में बाद के संशोधनों द्वारा इस अविध को बढ़ा दिया गया है।

अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों के लिए प्रावधान करता है, और ऐसे दावों के संरक्षण के संबंध में प्रावधान करता है।

कुल मिलाकर, भारत के संविधान का भाग XVI अनुसूचित जाति और जनजाति, एंग्लो-इंडियन और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों सिहत विभिन्न हाशिए और ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के अधिकारों और हितों के बारे में प्रावधान करता है, और इसका उद्देश्य सुरक्षा और प्रचार को सुनिश्चित करना है उनके अधिकार और हित।

